अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 92 | श्री विजय पुरम, सोमवार, 06 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ज्ञान भारतम् मिशन

पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय धरोहर की पहचान, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण हेतु केंद्रशासित प्रदेश स्तर की पहल

द्वीपों की विरासत को संरक्षित करने हेतु लोगों से पांडुलिपियाँ साझा करने की अपील

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम् मिशन प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य देशभर में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहों में उपलब्ध पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण तथा उन्हें सुलभ बनाना है। युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और प्राचीन ज्ञान को वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने भी तीनों ज़िलों में पुरानी पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर एक मिशन प्रारंभ किया है। इस पहल के अंतर्गत, निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐतिहासिक दस्तावेज़, मानचित्र और पुरानी तस्वीरें कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराएँ, ताकि उन्हें ज्ञान भारतम् सर्वे ऐप में अपलोड किया जा सके।

कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वीपों की अभिलेखीय धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में विभाग आम जनता, संस्थानों, विद्वानों एवं संग्रहकर्ताओं से निम्न प्रकार से सहयोग करने की अपील करता है:

- ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय सामग्री का दान या साझा करना।
- व्यक्तियों या संस्थाओं के पास उपलब्ध ऐसी सामग्री की जानकारी प्रदान करना।
- द्वीपों से संबंधित दुर्लभ एवं मूल्यवान अभिलेखों की पहचान एवं दस्तावेज़ीकरण में सहयोग करना।

प्रशासन आश्वासन देता है कि ऐसी सामग्री के संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी। योगदानकर्ताओं को उचित मान्यता दी जाएगी तथा सामग्री का स्वामित्व मूल धारकों के पास ही रहेगा। केवल संरक्षण एवं शोध के उद्देश्य से उसकी डिजिटल प्रतियाँ सुरक्षित की जाएँगी।

इच्छुक व्यक्ति पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय सामग्री का विवरण कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को सेल्यूलर जेल परिसर स्थित कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं या फोन नंबर 234775, 9476037145 अथवा ईमेल **cellularjailandaman@gmail.com** एवं **artand.culture@and.nic.in** पर संपर्क कर

सकते हैं। इस पहल में योगदान देकर नागरिक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध और विविध विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए, हम सभी मिलकर अपने द्वीपों की आवाज़, स्मृतियों और इतिहास को संरक्षित करें।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विविध संस्कृतियों,

शेष पृष्ठ 4 पर

आईडीई बूटकैम्प 2026 का शुभारंभ आज: नवाचार और उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अपने इनोवेशन सेल के माध्यम से 6 अप्रैल, 2026 को इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप (आईडीई) बूटकैम्प 2026 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करने जा रही है। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य देशभर के विद्यार्थियों में नवाचार, डिज़ाइन सोच और उद्यमिता क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह 5 दिवसीय बूटकैम्प तीन चरणों में देशभर के 30 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिससे व्यापक पहुंच और क्षेत्रीय विविधता सुनिश्चित होगी। पहला चरण 6 से 10 अप्रैल, 2026 तक 13 स्थानों पर आयोजित होगा।

इस कार्यक्रम में लगभग 6,500 विद्यार्थियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों की टीमें शामिल होंगी। इनमें

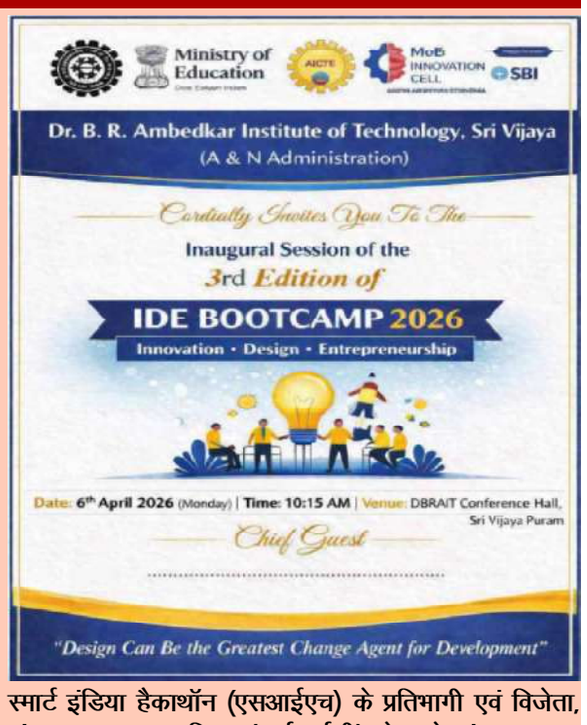

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच) के प्रतिभागी एवं विजेता, संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) से जुड़े संस्थान तथा वे छात्र शामिल होंगे जिनके पास नवाचारी विचार या प्रोटोटाइप हैं, जिन्हें डिज़ाइन सुधार, एर्गोनॉमिक्स संवर्धन और निवेश के लिए प्रस्तुति (पिचिंग) संबंधी मार्गदर्शन की

शेष पृष्ठ 4 पर

महिला सशक्तिकरण की मिसाल

पोल्ट्री फार्मिंग से आत्मनिर्भर बनीं श्रीमती अलो मंडल

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

नॉर्थ बंडूर की 50 वर्षीय निवासी श्रीमती अलो मंडल समर्पण, नवाचार और विभागीय सहयोग के माध्यम से पोल्ट्री फार्मिंग को एक स्थायी और लाभकारी आजीविका में बदलने का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी हैं। शुरुआत में उन्होंने केवल व्यक्तिगत रुचि के तौर पर देसी मुर्गियों का पालन किया, लेकिन जल्द ही अधिक आय की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने वनराजा नस्ल की मुर्गियों को अपनाया, जो अंडा और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहयोग से उन्हें डॉलीगंज स्थित केंद्रीय हैचरी से 200 वनराजा चूजे प्राप्त हुए। विभाग द्वारा उन्हें निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन, समय-समय पर सलाह तथा सभी शंकाओं का समाधान प्रदान किया गया, जिससे वे वैज्ञानिक तरीके से बैकयार्ड प्रणाली के तहत मुर्गी पालन कर सकीं।

श्रीमती मंडल अपने घर के आसपास बैचों में मुर्गियों को खुला विचरण करने देती हैं, जिससे चारे की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है और पक्षियों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अपनी नवाचारी सोच और संसाधनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने पोल्ट्री शेड की साइड दीवारें मछली पकड़ने के जाल से तैयार की हैं, जो कम लागत में बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करती हैं और निर्माण खर्च को काफी कम करती हैं।

उनकी सफलता की कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि उचित प्रशिक्षण और संसाधनों के सहयोग से छोटे स्तर पर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से स्थिर आय अर्जित की जा सकती है और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वीपों में महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण चूजों की आपूर्ति, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि स्वरोज़गार और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। (स्रोतः पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग)

'कालापानी ट्रेल' हेरिटेज वॉक का आयोजनः द्वीपों की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू हुए प्रतिभागी

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने 'इंटैच' अण्डमान तथा निकोबार अध्याय के सहयोग से गत शनिवार की सुबह एक और हेरिटेज वॉक 'कालापानी ट्रेल' का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य द्वीपों की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना तथा पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों और विरासत प्रेमियों को एक जीवंत अनुभव प्रदान करना था।

यह वॉक मज़ार पहाड़ से शुरू होकर लेडीज कंविक्ट बैरक, ब्लेसिंगटन, गवर्नमेंट प्रेस, जेएनआरएम जैसे ऐतिहासिक स्थलों से होते हुए बैटल ऑफ अबर्डीन मेमोरियल पर समाप्त हुई। इस वॉक में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के बीबीए के छात्र, अण्डमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, अण्डमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदस्य, भारतीय नौसेना के प्रतिभागी तथा केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक शामिल हुए।

इस हेरिटेज वॉक के माध्यम से प्रतिभागियों को श्री विजय पुरम के विभिन्न स्थलों के इतिहास, वास्तुकला और उनसे जुड़ी कहानियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ, वहीं स्थानीय गाइड और पर्यटन के छात्र-छात्राओं को इन सांस्कृतिक अनुभवों को सीखने और आगे बढ़ाने का अवसर मिला। 'इंटैच', अण्डमान तथा निकोबार अध्याय की संयोजक श्रीमती सम्हिता वेदा

शेष पृष्ठ 4 पर

आगामी 17 अप्रैल से शुरू होने वाले 'द्वीप खाद्य महोत्सव-2026' के लिए इच्छुक विक्रेताओं से आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का पर्यटन विभागआगामी द्वीप खाद्य महोत्सव 2026 में भाग लेने के लिए खाद्य विक्रेताओं, राज्य संघों, स्वयं सहायता समूहों, होटल मालिकों, रेस्तरां मालिकों, खानपान संस्थानों और गृहिणियों से आवेदन आमंत्रित करता है। यह महोत्सव 17 से 19 अप्रैल, 2026 तक यहां के वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित करता है, जिससे खाद्य विक्रेताओं को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने, व्यापक दर्शकों से जुड़ने और अपनी दृश्यता और व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक मंच मिलता है।

गुणवत्ता, स्वच्छता और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले इच्छुक विक्रेताओं को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र और विस्तृत दिशा-निर्देश सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, श्री विजयपुरम के संचालन इकाई से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महोत्सव तीनों दिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जो स्वादिष्ट भोजन, जीवंत वातावरण, संगीत और उत्साही भीड़ से भरी खुशनुमा शामों का वादा करता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, स्टॉलों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। स्टॉलों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र और नियम व शर्तें सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, श्री विजयपुरम के संचालन अनुभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किए जा सकते हैं। चयनित राज्य संघों, स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल बिना किराए के आवंटित किए जाएंगे।

शेष पृष्ठ 4 पर

टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0

मध्य अण्डमान में स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित

मायाबंदर, 5 अप्रैल

टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत मध्य अण्डमान के लॉन्ग आइलैंड, रंगत सब्ज़ी बाज़ार और बाराटांग में आयुष्मान आरोग्य शिविरों एवं जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिससे तपेदिक (टीबी) की जांच और जन-जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्तर व मध्य अण्डमान के डीटीओ से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 30 मार्च को ग्राम पंचायत लॉन्ग आइलैंड के प्लॉट एरिया एवं सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के दौरान कुल 100 छाती के एक्स-रे एवं एनसीडी (गैर-संचारी रोग) जांच की गई तथा आगे की जांच हेतु 25 बलगम (स्पुटम) नमूने एकत्र किए गए।

शेष पृष्ठ 4 पर

मत्स्य क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता की सराहनीय पहल

बेंगलुरु के गियर इंटरनेशनल इनोवेटिव स्कूल के 80 छात्रों ने पारंपरिक नौकाओं के पुनर्स्थापन में दिया योगदान

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

मत्स्य कल्याण में सामुदायिक सहभागिता को उजागर करने वाली एक सराहनीय पहल के तहत, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग ने दक्षिण अण्डमान के गुप्तापाड़ा स्थित फिश लैंडिंग सेंटर में एक अनूठा सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बेंगलुरु के गियर इंटरनेशनल इनोवेटिव स्कूल के 80 छात्रों

ने सामुदायिक भागीदारी के रूप में पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पुनर्स्थापन में योगदान दिया।

शेष पृष्ठ 4 पर

पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय धरोहर की पहचान, ——————पृष्ठ 1 का शेष

औपनिवेशिक इतिहास, जनजातीय परंपराओं और समुद्री विरासत का अद्वितीय संगम है, जो भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन काल से यहाँ निवास कर रही जनजातीय समुदायों से लेकर औपनिवेशिक काल में सेल्यूलर जेल की स्थापना और स्वतंत्रता के बाद विकसित होते जीवंत द्वीपीय समाज तक, इन द्वीपों की समृद्ध विरासत यहाँ के लोगों, परंपराओं और ऐतिहासिक अभिलेखों में परिलक्षित होती है।

इस अमूल्य धरोहर के संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पुस्तकें, व्यक्तिगत डायरी, पत्र, फोटोग्राफ/नेगेटिव, मानचित्र, प्रशासनिक अभिलेख, ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग तथा अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं, जो इन द्वीपों के जीवन और इतिहास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। व्यक्तियों, परिवारों, संस्थानों और संगठनों के पास सुरक्षित ऐसी सामग्री अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सामाजिक–सांस्कृतिक विकास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रवासन पैटर्न और जनजातीय परंपराओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राचीन पांडुलिपियाँ और दुर्लभ अभिलेख हमारी बौद्धिक परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक स्मृति के अमूल्य साक्ष्य हैं। उनका संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना हमारी साझा ज़िम्मेदारी है। लोगों से भारत सरकार के इस मिशन में आगे आकर योगदान देने की अपील की गई है।

'कालापानी ट्रेल' हेरिटेज वॉक का आयोजनः ——————पृष्ठ 1 का शेष

आचार्य ने अपनी प्रभावशाली कहानी–वाचन शैली के माध्यम से इस वॉक को समय की एक जीवंत यात्रा में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर ऐतिहासिक घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अनुभव शैक्षणिक होने के साथ–साथ अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बन गया।कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री चंचल सिंघा रॉय ने भी इस वॉक में भाग लिया और 'द कीपर ऑफ सिल्वर ब्रेड' नामक एक लघु कहानी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया तथा यह भी बताया कि कहानियों को जीवित रखना क्यों आवश्यक है।

आईडीई बूटकैम्प 2026 का शुभारंभ आजः नवाचार ——————पृष्ठ 1 का शेष

आवश्यकता है। पूरे बूटकैम्प के दौरान संकाय मार्गदर्शक (फैकल्टी मेंटर्स) छात्र टीमों का मार्गदर्शन करेंगे।

विशेष रूप से, बूटकैम्प के आयोजन स्थल जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे टियर–2 और टियर–3 शहरों सहित विविध क्षेत्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। पहली बार यह बूटकैम्प लेह (लद्दाख) और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आयोजित किया जा रहा है, जो दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक नवाचार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'डीब्राइट' से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री एल. कुमार (आईएएस), सचिव (शिक्षा) कल 6 अप्रैल, 2026 को यहां के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में इस बूटकैम्प के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यह पहल द्वीपों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और सशक्त बनाने के साथ–साथ युवाओं की प्रतिभा को निखारने तथा उनके विचारों को प्रभावशाली समाधानों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आगामी 17 अप्रैल से शुरू होने वाले 'द्वीप खाद्य महोत्सव ——पृष्ठ 1 का शेष

श्रेणियाँ	3 दिनों के लिए सभी करों सहित स्टॉल का किराया	सुरक्षा जमा
लाइव किचन	4,500 रुपये प्रति दिन की दर पर प्रत्येक का मूल्य 13,500 रुपये	प्रत्येक स्टॉल का शुल्क 6,000 रुपये है
पका हुआ/घर का बना खाना/स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ।	प्रत्येक की कीमत 10,500 रुपये है	
मनोरंजक खेल/ बाउंसी आदि के लिए खुला क्षेत्र	486.11 रुपये प्रति वर्ग मीटर	

क्र.सं.	कार्यक्रम	संभावित तिथियां
1.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	09/04/2026 शाम 3 बजे
2.	समिति द्वारा स्टॉल का आवंटन	12/04/2026
3.	आवंटन पत्र जारी करना	12/04/2026

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्रीमती राबिया मुस्तफा, प्रबंधक (संचालन) से मोबाइल नंबर 9933255364पर संपर्क किया जा सकता है।

बेंगलुरु के गियर इंटरनेशनल इनोवेटिव स्कूल ——————पृष्ठ 1 का शेष

यह कार्यक्रम डिस्कवर अण्डमान हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर मछुआरों की आजीविका संपत्तियों को सुदृढ़ करना था। विभाग द्वारा चिन्हित जरूरतमंद मछुआरों की तीन बिना मोटर वाली डोंगियों को मरम्मत कार्य हेतु छात्रों को सौंपा गया।मत्स्य विभाग के अधिकारियों, जिनमें सहायक मत्स्य रक्षक श्री नदीम शामिल थे, की देखरेख में छात्रों ने नौकाओं की सफाई, छोटी–मोटी मरम्मत, रखरखाव और समुद्री गुणवत्ता वाले पेंट से रंगाई का कार्य किया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नौकाओं के उचित रखरखाव और रंग–कोडिंग के महत्व के बारे में भी जागरूक किया, जो मत्स्य क्षेत्र में पहचान, सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पहल से न केवल नौकाओं की कार्यक्षमता में सुधार हुआ, बल्कि लाभार्थी मछुआरों की आय बढ़ाने में भी सीधा योगदान मिला। इस दौरान स्थानीय मछुआरों ने भी छात्रों के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता की और पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों तथा आजीविका बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत गुप्तापाड़ा के प्रधान श्री दुर्लभ दास के उत्साहवर्धन से हुई, जिन्होंने मत्स्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समुदाय और युवा शिक्षार्थियों के बीच की दूरी को कम करने के साथ–साथ मत्स्य क्षेत्र की ज़मीनी जरूरतों को भी पूरा करती है। मत्स्य विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मछुआरों ने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुनर्स्थापित नौकाएं उनके दैनिक मछली पकड़ने के कार्य में तुरंत सहायक होंगी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने इस प्रकार के सहयोगात्मक प्रयासों को सतत मत्स्य विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण और युवाओं में इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। यह पहल इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब शैक्षणिक पहुंच कार्यक्रमों को मत्स्य विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है, तो इससे तटीय समुदायों को ठोस लाभ मिलता है और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों में ज़िम्मेदारी और जागरूकता भी विकसित होती है।

इग्नू 7 अप्रैल को आयोजित करेगा 39वां दीक्षांत समारोह

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का 39वां दीक्षांत समारोह मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को सुबह 11 बजे इग्नू मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर में एक साथ आयोजित किया जाएगा। मुख्यालय में भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और दीक्षांत भाषण देंगे।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में यह दीक्षांत समारोह श्री विजय पुरम स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. एस. दिनेश कन्नन (आईएफएस) विशिष्ट अतिथि के रूप में तथा डॉ. सी. शिवपेरुमन, निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विशेष अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी शिक्षार्थी को 39वें दीक्षांत समारोह के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, तो वे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, श्री विजय पुरम, पिन कोड 744103 लैंडलाइन नंबर 03192–230111/242888 या ईमेल **rcportblair@ignou.ac.in** से संपर्क कर सकते हैं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न

श्री विजय पुरम, 5 अप्रैल

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के क्षमता विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से खंड स्तर पर तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना, लैंगिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना तथा पंचायत शासन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समापन सत्र में फेरारगंज की बीडीओ श्रीमती ललिता टिग्गा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं नेतृत्व पुरस्कार वितरित कर उनके सक्रिय सहभागिता की सराहना की। इससे पूर्व स्वागत संबोधन में सुश्री साक्षी साहा (बीपीएम) ने महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे समावेशी एवं प्रभावी ज़मीनी स्तर का प्रशासन सुनिश्चित होता है।

विश्व होम्योपैथी दिवस पर स्वच्छता अभियान एवं महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित

मायाबंदर, 5 अप्रैल

आगामी विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में डॉ. आरपी अस्पताल, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान के होम्योपैथी स्कंध द्वारा ग्राम पंचायत पोकाडेरा के सहयोग से बालूडेरा तट पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्यमय वातावरण बनाए रखने में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सभा को संबोधित करते हुए पीआरआई सदस्य ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक ज़िम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अभियान में डॉ. आरपी अस्पताल की चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम, जिसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. क्रिस्टीना एवं डॉ. दिव्या सिंह (चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी) शामिल थीं, ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे कार्यक्रम सफल और प्रभावी बना।

मध्य अण्डमान में स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता ——————पृष्ठ 1 का शेष

समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें टीबी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में प्रभावी संदेश दिए गए। इस अवसर पर लॉन्ग आइलैंड पंचायत के प्रधान श्री कामराज भी उपस्थित थे। अभियान को आगे बढ़ाते हुए 31 मार्च को बाराटांग के अडाजिग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक भवन में अन्य आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 36 एक्स–रे जांच की गई, जिनमें से 15 लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान की गई और उनके बलगम नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए।

साथ ही, जन भागीदारी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता को शामिल कर टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। उत्तर व मध्य अण्डमान की ज़िला टीबी अधिकारी डॉ. क्रिस्टीना रॉसिटी ने टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत 100 दिवसीय अभियान की जानकारी दी।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

1 अप्रैल, 2017 से पहले के निवेश के ट्रांसफर से होने वाली आय पर नहीं लागू होगा जीएएआरः सीबीडीटी

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स नियमों में संशोधन करते हुए जनरल एंटी–अवॉइडेंस रूल्स (जीएएआर) के लागू होने को लेकर स्पष्टता दी है। यह कदम टैक्स से बचने से जुड़े नियमों में अस्पष्टता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से पहले किए गए निवेश के ट्रांसफर से होने वाली आय पर जीएएआर लागू नहीं होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

यह स्पष्टीकरण निवेशकों को, खासकर पुराने निवेश (लेगेसी इन्वेस्टमेंट) के मामलों में, अधिक स्पष्टता और भरोसा देगा, क्योंकि इससे जीएएआर के दायरे को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल के खिलाफ दिए गए फैसले के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट से एग्जिट पर हुए मुनाफे पर आयकर विभाग के टैक्स लगाने के अधिकार को सही ठहराया था।

इस संशोधन को सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें टैक्स चोरी रोकने के उपायों और एक स्थिर व पूर्वानुमान योग्य टैक्स सिस्टम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, नए वित्त वर्ष से नया आयकर कानून लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ली है, और इसमें अनुपालन, शब्दावली और टैक्स प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं।

नए ढांचे के तहत एक बड़ा बदलाव 'फाइनेंशियल ईयर' (एफवाई) और 'असेसमेंट ईयर' (एवाई) की जगह एक ही 'टैक्स ईयर' को लागू करना है, जिससे रिटर्न फाइल करना आसान होगा और टैक्सपेयर्स के लिए स्पष्टता बढ़ेगी। इसके साथ ही, इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समय–सीमा में भी बदलाव किया गया है। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन पहले की तरह ही रहेगी, जबकि सेल्फ–एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स जैसे नॉन–ऑडिट मामलों में अब 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

इस बीच, यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) में ट्रेडिंग पर लगने वाले शुल्क बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाया गया है। एक और बड़े बदलाव के तहत, अब कंपनियों के शेयर बायबैक पर टैक्स को 'डिविडेंड' की बजाय 'कैपिटल गेन' के रूप में लिया जाएगा, जिससे प्रमोटर्स और रिटेल निवेशकों, दोनों पर असर पड़ेगा।

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भारत जनगणना 2027 के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

भारत सरकार ने मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को देश की पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वे अपनी प्रभावशाली रेत कला के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, और वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग जनगणना के आंकड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे। इसके साथ ही, यह पूरे भारत के लोगों को इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित करेगा।

वे ओडिशा राज्य के एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार हैं। उन्हें कला को सामाजिक जागरूकता और अभियानों के साथ जोड़ने के लिए भी व्यापक रूप से पहचाना जाता है। कला और अपनी अनूठी कलाकृतियों के माध्यम से सार्वजनिक संदेश देने में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2014 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

उन्होंने 2017 में पुरी समुद्र तट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत का किला बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसकी ऊँचाई 48 फीट 8 इंच थी। पिछले कुछ वर्षों में, उनकी कलाकृतियों ने जलवायु परिवर्तन और COVID–19 जागरूकता जैसे प्रमुख मुद्दों को उजागर किया है, जिससे वे भारत की बड़ी जनगणना 2027 का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आदर्श विकल्प बन गए हैं।

जनगणना 2027 की शुरुआत इस बात का संकेत है कि भारत जिस तरह से जनसांख्यिकीय डेटा इकट्ठा और प्रबंधित करता है, उसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पहली बार, गणना करने वाले पारंपरिक कागज़ी तरीकों के बजाय स्मार्टफोन–आधारित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे।

इस डिजिटल बदलाव से सटीकता और कार्यक्षमता में सुधार होने, साथ ही डेटा प्रोसेसिंग में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह रियल–टाइम मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, नागरिकों के पास अब 'सेल्फ–एन्यूमरेशन पोर्टल' के माध्यम से भाग लेने का विकल्प भी होगा; भारत की जनगणना के इतिहास में यह सुविधा पहले कभी शुरू नहीं की गई थी। जनगणना दो व्यवस्थित चरणों में आयोजित की जाएगी, ताकि व्यापक डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जा सके

भारत के गगनयान मिशन ने लद्दाख की बेहद कठिन परिस्थितियों में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

भारत के गगनयान मिशन ने लद्दाख की बेहद कठिन परिस्थितियों में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है, जिसे 'मिशन मित्र' नाम दिया गया है। इस मिशन का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मिशन के सदस्यों की शारीरिक सहनशक्ति, टीम वर्क और मानसिक मज़बूती का परीक्षण करना है। चूंकि भारत लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यात्री न केवल शारीरिक रूप से प्रशिक्षित हों, बल्कि अंतरिक्ष में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार हों।

'मिशन मित्र' इस समय लद्दाख के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है।

लद्दाख अपने कठोर मौसम, ऑक्सीजन के कम स्तर और एकांत के लिए जाना जाता है।

ये परिस्थितियाँ काफी हद तक वैसी ही हैं, जैसी अंतरिक्ष में चुनौतियों का सामना करते समय होती हैं।

इस कार्यक्रम का संचालन ISRO के 'ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट सेंटर' द्वारा विभिन्न शोध टीमों और विशेषज्ञों के सहयोग से किया जा रहा है।

इस मिशन में वे चार चयनित अंतरिक्ष यात्री हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने लेह में जाकर वहाँ के वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

मिशन मित्रा का पूरा नाम 'मैपिंग ऑफ़ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट' है, और इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के पारंपरिक प्रशिक्षण की तुलना में, यह मिशन तनावपूर्ण स्थितियों में उनके मानसिक लचीलेपन और एकांत वातावरण में टीम के आपसी तालमेल पर विशेष रूप से केंद्रित है।

इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करना है, जहाँ अकेलापन, संचार में देरी और सीमित संसाधन मिशन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। मिशन मित्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स बहुत खराब हालात में रहेंगे और काम करेंगे और एक्सपर्ट्स उन पर करीब से नज़र रखेंगे।

ये रिसर्चर्स स्टडी करेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स दबाव में कैसे

बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं और भरोसा बनाए रखते हैं। यह मिशन ठंडे तापमान, कम ऑक्सीजन लेवल और लंबे समय तक अकेले रहने पर उनके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ट्रैक करेगा।

इस तरह की सिमुलेशन फीलिंग यह भी टेस्ट करेगी कि एस्ट्रोनॉट्स मुश्किलों और असली स्पेस मिशन में महसूस होने वाली स्थितियों के बावजूद ग्राउंड टीमों के साथ कितने असरदार तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। मिशन मित्रा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के CAVES एक्सपेरिमेंट के इंटरनेशनल प्रोग्राम से प्रेरणा लेता है।

उस एक्सपेरिमेंट में एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस के माहौल की नकल करने के लिए ज़मीन के नीचे की गुफाओं में ट्रेनिंग ली है। इसी तरह, भारत अब नए तरीके अपना रहा है और एस्ट्रोनॉट की तैयारी के लेवल को बेहतर बनाने के लिए असल दुनिया के माहौल को साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिला रहा है।

लद्दाख अंतरिक्ष का सिमुलेशन करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सबसे करीबी वातावरणों में से एक प्रदान करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर कम है और यहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है।

ये स्थितियाँ शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेंगी कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक चलने वाले मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्री किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना और साथ ही एक उन्नत क्रू सुरक्षा प्रणाली विकसित करना है।

क्या आप जानते हैं एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी का फुलफॉर्म, एक–दूसरे से कितना अलग होती हैं ये गैसें

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

अमेरिका–ईरान युद्ध के कारण गैस से जुड़े शब्द जैसे स्च्ळ, च्छळ, ब्छळ और स्छळ बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं. आमतौर पर एलपीजी और सीएनजी का नाम ही लोग लेते थे लेकिन इनसे मिलते जुलते और भी कई शब्द हैं जो गैस से संबंधित हैं. क्या आप जानते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है और ये एक–दूसरे से कैसे अलग होते हैं.

LPG – Liquefied Petroleum Gas-

यह गैस लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है. इसका प्रयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है. स्च्ळ सिलेंडर लगभग हर घर में उपयोग होता है. आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी ही होती है. कुकिंग गैस के अलावा इस गैस का प्रयोग कुछ छोटे उद्योगों में भी होता है.

PNG – Piped Natural Gas-

यह गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाई जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि कई घरों में गैस का कनेक्शन लगा होता है, जहां पाइप द्वारा कुकिग गैस आती है. यह पीएनजी गैस होती है. इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है. यह बहुत सुरक्षित गैस मानी जाती है और किफायती होती है.

CNG – Compressed Natural Gas-

यह गैस हाई प्रेशर में कंप्रेस की जाती है. इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है. जैसे आपने सीएनजी से चलने वाली कार, ऑटो, बस आदि देखे होंगे. इस गैस से वाहन चलाने पर पेट्रोल–डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण होता है.

LNG – Liquefied Natural Gas-

यह प्राकृतिक गैस का लिक्विड रूप होता है. इस गैस को बहुत कम तापमान पर स्टोर किया जाता है. करीबन –162C पर इसे स्टोर रखना होता है. इसका उपयोग इंडस्ट्रीज, बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटरनेशनल गैस ट्रांसपोर्ट आदि में किया जाता है.

जब दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी 24 दिनों तक रोज 16 से 19 किलोमीटर चलते थे पैदल

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

इतिहास में आज का दिन बेहद खास है. आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 'दांडी मार्च' की शुरुआत की थी. यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के रूप में माना जाता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी. नमक सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ने 24 दिनों तक रोज औसतन 16 से 19 किलोमीटर पैदल यात्रा की. दांडी यात्रा से पहले बिहार के चंपारन में सत्याग्रह के दौरान भी गांधीजी बहुत पैदल चले थे. नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये प्रमुख आंदोलनों में से एक था. महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था. दांडी मार्च जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया आंदोलन था.

गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 कि.मी. दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया. 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल, 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्रतट पर नमक कानून को तोड़ा. महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, वांज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा

के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था. नवसारी से दांडी का फासला लगभग 13 मील का है.

बता दें कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई थी परंतु पीछे नहीं मुड़े थे. इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. ये आंदोलन पूरे एक साल चला और 1931 को गांधी–इर्विन समझौते से खत्म हो गया.

इतिहास के पन्नों में 06 अप्रैलः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, देश की राजनीति में नया अध्याय

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल की तारीख विशेष महत्व रखती है। इसी दिन वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई।

भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ में थीं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जनसंघ ने लंबे समय तक देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और वैचारिक आधार तैयार किया।

वर्ष 1975 में लागू आपातकाल के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया। 1977 में जनसंघ सहित कई दलों का विलय होकर जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने आम चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया।

हालांकि, आंतरिक मतभेदों के चलते जनता पार्टी अधिक समय तक एकजुट नहीं रह सकी। अंततः 1980 में इसका विघटन हुआ और उसी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भाजपा ने अपने गठन के बाद धीरे–धीरे संगठन को मजबूत किया और आज यह देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक बन चुकी है। 06 अप्रैल का दिन इसलिए भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1606– राजकुमार खुसरो ने अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की।

1896– आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआत।

1906– पहले एनिमेटिड कार्टून के लिए कॉपीराइट हासिल किया गया।

1917– प्रथम विश्वयुद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1919– महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया।

1925– विमान में पहली बार फिल्म दिखाई गई, विमान ब्रिटिश एयरवेज का था।

1930– महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत की मांग के साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन आन्दोलन छेड़ा।

1936– एएनपी ने एम्स्टर्डम में पहली टेलेक्स सेवा शुरू की।

1942– जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर बमबारी की।

1955– अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया।

1957– सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।

1966– भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जलडमरूमध्य तैर कर पार किया।

1980– भारतीय जनता पार्टी की स्थापना।

1982– दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित उपनिवेश फ़ाकलैंड पर अर्जेन्टीना ने अधिकार किया।

1985– पाब्लो पिकासो के समकालीन विश्वविख्यात कलाकार मार्क शागल का पेरिस में देहांत।

1998– गोरी प्रक्षेपास्त्र का पाकिस्तान द्वारा सफल प्रक्षेपण।

1999– नेपाल में पुनः पांच सौ रुपये के भारतीय नोट चलाने की घोषणा।

2000– कराची की एक अदालत ने आतंकवाद व विमान अपहरण के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ को उम्र क़ैद की सजा सुनायी।

2020 – कोरोना वायरस संक्रमण से दुनियाभर में 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा साढ़े चार हजार के पार पहुंचा।

2024 – अतंरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने मिशन के बाद दो महिला और एक पुरुष यात्री रूसी अंतरिक्ष कैप्सूल के जरिए कजाखस्तान पहुंचे।

गैजेट रेडिएशन से सुरक्षा है बेहद जरूरी, बच्चों का मानसिक विकास हो सकता है प्रभावित

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

आज की जीवनशैली में सारा काम गैजेट पर निर्भर हो गया है। हर वक्त हमेशा गैजेट से घिरे रहते हैं, बात चाहे ऑफिस की हो या फिर घर की। घर पर टीवी, एसी और फोन और ऑफिस में लगातार कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के सामने बैठना ही पड़ता है। ऐसे में गैजेट रेडिएशन से शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन शरीर को अंदर से हानि पहुंचाते हैं। आज के समय में रेडिएशन से सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज हम आपको गैजेट रेडिएशन से सुरक्षा के बारे में बताएंगे।

आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और वाई–फाई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इनका ज्यादा और गलत इस्तेमाल शरीर पर असर डाल सकता है। थोड़ी सावधानी अपनाकर आप खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो हमेशा माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। इससे शरीर के बीच में एक सीमित दूरी बन जाती है और रेडिएशन का असर कम हो जाता है।

दूसरा, लैपटॉप को गोद में रखकर काम करने से बचें; हमेशा टेबल का इस्तेमाल करें। इससे रेडिएशन सीधा शरीर को नहीं छूती। अपने और मेज के बीच में हमेशा एक फीट की दूरी बनाकर रखें। इससे आंखें और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही, फोन को भी हमेशा खुद से सटाकर न रखें।

अक्सर लोग फोन को पॉकेट में रखते हैं और सोते वक्त भी अपने पास रखते हैं। इससे दिल और दिमाग दोनों को क्षति पहुंचती है। अगर घर पर वाई–फाई लगता है तो कोशिश करें कि वाई–फाई के राउटर को बाहर लगवाने की कोशिश करें। इससे घर में रेडिएशन का स्तर कम होगा और हवा भी साफ रहेगी। राउटर से निकलने वाली किरणें नींद में खलल डालती हैं और इससे मस्तिष्क की नसों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

सोते समय कोशिश करें कि फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें। ऐसा करने से रेडिएशन का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि बच्चों को गैजेट से दूर रखें। गैजेट के इस्तेमाल से बच्चों का मानसिक स्तर कमजोर होता है और विकास में भी बाधा होती है।

शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

शिक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था घोषित किया है, जिससे यह पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों की पेशकश करने और डिग्री प्रदान करने में सक्षम हो गया है।

30 मार्च, 2026 की अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस वर्ष जनवरी में एनसीईआरटी – एक नोडल स्कूल शिक्षा निकाय – को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने एनसीईआरटी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया।

इस अधिसूचना के तहत एनसीईआरटी और उसके छह क्षेत्रीय संस्थानों को यह दर्जा दिया गया है, बशर्ते कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाए।

ये शर्तें एनसीईआरटी को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से रोकती हैं जो "वाणिज्यिक" और "लाभ कमाने वाली" प्रकृति की हो, और यह अनिवार्य करती हैं कि सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक निकायों या परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप हों।

अधिसूचना में एनसीईआरटी को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह परिसर से बाहर या विदेशी परिसरों में नए कार्यक्रम "केवल यूजीसी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही" शुरू करे। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि एनसीईआरटी अनुसंधान कार्यक्रम, डॉक्टरेट कार्यक्रम और "नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम" शुरू करने के लिए "उचित कदम उठाएगा"।

इसमें आगे कहा गया है कि संस्थान को वर्तमान में उभर रहे नए क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यूजीसी के दिशानिर्देशों और विनियमों तथा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का "प्रयास" करना चाहिए।

मंत्रालय ने आगे कहा है कि एनसीईआरटी को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को स्वयं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे।

सरकार ने एनसीईआरटी को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग में भाग लेना शुरू करने का निर्देश दिया है और उसे अनिवार्य रूप से अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) बनाने, अपने छात्रों की पहचान दर्ज करने और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करने के लिए कहा है, जिसे एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

गैस आपूर्ति के लिए सरकार का बड़ा फैसलाः 5 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए अब एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

पश्चिम एशिया में जारी तनावों के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब 5 किलो एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता केवल वैध पहचान पत्र (आईडी) दिखाकर इसे नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं।

सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंकाओं के बीच देश में ईंधन और ऊर्जा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा, "5 किलो एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) एलपीजी सिलेंडर नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर पर उपलब्ध हैं और इन्हें किसी भी वैध आईडी दिखाकर खरीदा जा सकता है। इसके लिए एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं है।"

अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए लिया गया है, जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं होते ताकि उन्हें खाना पकाने के लिए गैस आसानी से मिल सके। 23 मार्च से अब तक ऐसे करीब 5.7 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जिसमें हाल ही में एक दिन में 71,000 से ज्यादा सिलेंडर की बिक्री हुई है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें। सरकार ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और देश भर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, हालांकि कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण भीड़ देखने को मिली है।

सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है, रिफाइनरियों को पूरी क्षमता पर चलाया जा रहा है और घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही मांग को नियंत्रित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे एलपीजी बुकिंग साइकिल बढ़ाना और पीएनजी, केरोसिन व इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन देने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है। हाल ही में 3,700 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और गड़बड़ी करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

ईरान युद्ध के बीच कुकिंग गैस पर निर्भरता घटाने की तैयारी, सरकार घरेलू इंडक्शन हीटर उत्पादन बढ़ाने पर कर रही फोकस

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

केंद्र सरकार कुकिंग गैस की खपत कम करने के लिए अब इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस दिशा में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव, विद्युत सचिव और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक सहित शीर्ष अधिकारियों ने एक उच्चस्तरीय बैठक की।

इस बैठक में ईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं को देखते हुए इंडक्शन हीटर और कुकिंग उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कुकिंग गैस की खपत कम की जा सके। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से इंडक्शन हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो भारत को संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब सरकार लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की संभावना को देखते हुए आयात पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रही है। खासतौर पर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में बाधा को लेकर चिंता जताई जा रही है। सरकार पहले ही कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर चुकी है, ताकि सप्लाई बनी रहे और लागत का दबाव कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मुख्य फोकस जरूरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आयात पर निर्भरता कम करना है।

कतर में एक बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) प्लांट को नुकसान पहुंचने के बाद मध्य पूर्व से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद होने की स्थिति में है, जहां से दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाई है और अब रूस के साथ–साथ नाइजीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां अमेरिका से भी गैस की आपूर्ति ले रही हैं।

इस बीच, पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी सेना अगले 2–3 हफ्तों तक ईरान पर 'बेहद कड़ा प्रहार' करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को 'स्टोन एजेज यानी पाषाण युग' (उनकी पुरानी स्थिति जहां वे असल में थे) में पहुंचा देगा।

नए लेबर कोड के तहत अब कुछ कर्मचारियों को एक साल के बाद भी मिलेगा ग्रेच्युटी का अधिकार

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कुछ योग्य कर्मचारियों को सिर्फ एक साल की लगातार सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार मिल सकता है, जबकि पहले इसके लिए 5 साल तक नौकरी करना जरूरी था।

नवंबर 2025 से लागू हुए इन नए श्रम कानूनों के अनुसार, फिक्स्ड–टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी पहले से मिलने लगेगी। हालांकि एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्थायी (परमानेंट) कर्मचारियों के लिए अभी भी 5 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है, लेकिन मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में छूट दी गई है।

फिक्स्ड–टर्म कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें कंपनियां एक तय समय के लिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करती हैं, जो आमतौर पर एक या दो साल का हो सकता है। अब ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार तय की जाएगी।

इन नए नियमों से देश के औपचारिक (फॉर्मल) सेक्टर के लाखों कर्मचारियों को नौकरी के बाद मिलने वाले लाभों तक पहुंच आसान हो सकती है। नए लेबर कोड के मुताबिक, ग्रेच्युटी की गणना वेतन के आधार पर होगी, जो कर्मचारी के कुल सीटीसी (कॉस्ट–टू–कंपनी) का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

श्रम मंत्रालय के अनुसार, वेतन में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (डीए), रिटेनिंग अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल होते हैं, जो कर्मचारी को दिए जाते हैं।

जिन कर्मचारियों का पहले बेसिक वेतन कम था, उनके लिए अब ग्रेच्युटी की रकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

ग्रेच्युटी एक कानूनी रूप से अनिवार्य एकमुश्त (लंप–सम) भुगतान होता है, जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसकी लंबी सेवा के सम्मान में देता है, आमतौर पर 5 साल की सेवा या रिटायरमेंट के बाद।

श्रम मंत्रालय ने अपने एफएक्यू में कहा है कि ग्रेच्युटी के ये नए नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं और संस्थानों को इसके लिए अपने अकाउंटिंग नियमों के अनुसार प्रावधान करना होगा।

इसका मतलब है कि 21 नवंबर 2025 या उसके बाद नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारी ही एक साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी का दावा कर सकेंगे।

सरकार ने फ्लाइट में 60 प्रतिशत मुफ्त सीट चयन अनिवार्य करने वाले आदेश को किया स्थगित

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

केंद्र सरकार ने फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने के अपने पहले के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जो 20 अप्रैल से लागू होने वाला था। नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भेजे गए एक पत्र में कहा कि इस फैसले की समीक्षा की गई है। यह समीक्षा फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद की गई, जिसमें इस नियम के ऑपरेशनल और कमर्शियल असर को लेकर सवाल उठाए गए थे।

एयरलाइंस ने कहा था कि यह नियम किराया ढांचे को प्रभावित कर सकता है और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ सिस्टम के अनुरूप नहीं है। सरकार ने कहा कि इन सभी पहलुओं को देखते हुए और मामले की विस्तृत समीक्षा होने तक 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने का प्रावधान फिलहाल अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, फ्लाइट की 20 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को शुल्क देना पड़ता है।

एयरलाइंस आमतौर पर सीट चयन के लिए 200 रुपए से लेकर 2,100 रुपए तक चार्ज करती हैं, जो सीट की लोकेशन और अतिरिक्त लेगरूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है। 18 मार्च को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी मूल निर्देश का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को दूर

करना था, खासकर सीट चयन जैसे सेवाओं पर ज्यादा शुल्क को लेकर।

मंत्रालय ने डीजीसीए के जरिए नए दिशा–निर्देश जारी किए थे, जिसमें एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठाने (अधिमानतः अगल–बगल की सीटों पर बैठाना) जैसे यात्री हित से जुड़े प्रावधान शामिल थे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है और भारतीय हवाई अड्डों पर रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आर्टेमिस–II मैनुअल पायलटिंग का सफल प्रदर्शन, फ्लाईबाई की तैयारी में जुटे एस्ट्रोनॉट्स

वॉशिंगटन, 05 अप्रैल।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन के चौथे दिन क्रू सदस्यों ने ओरियन यान में मैनुअल पायलटिंग का सफल प्रदर्शन पूरा कर लिया। यह मिशन चंद्रमा के चारों ओर घूमकर वापस पृथ्वी लौटने का परीक्षण है। क्रू ने मून फ्लाईबाई की योजना की भी समीक्षा की।

नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हैनसेन ने बारी–बारी से ओरियन यान को नियंत्रित किया। 41 मिनट तक उन्होंने दो अलग–अलग थ्रस्टर मोड का परीक्षण किया। इस परीक्षण से इंजीनियर्स को यान की पायलटिंग क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। सोमवार, 6 अप्रैल को अपने छह घंटे के फ्लाईबाई के दौरान वे तस्वीरें लेंगे और विश्लेषण करेंगे। फ्लाईबाई की अवधि 6 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे शुरू होगी।

मिशन कमांडर रीड वाइसमैन और पायलट विक्टर ग्लोवर इस प्रदर्शन को उड़ान के आठवें दिन यानी 9 अप्रैल को दोहराएंगे। इससे जमीनी टीम को यान के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं की बेहतर समझ मिल सकेगी।

क्रू ने चंद्र विज्ञान टीम द्वारा भेजी गई चंद्रमा की सतह की विशेषताओं की सूची की समीक्षा की। अब सोमवार 6 अप्रैल को छह घंटे की चंद्र फ्लाईबाई के दौरान वे इन स्थानों की तस्वीरें लेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। फ्लाईबाई दोपहर 2 बजकर 45 मिनट से शुरू होगी, इस दौरान ओरियन यान की मुख्य खिड़कियां चंद्रमा की ओर होंगी। इससे पहले क्रू ने ओरियन यान के सौर पैनल कैमरों का उपयोग करके कुछ सेल्फी लीं। ये तस्वीरें आने वाले दिनों में पृथ्वी पर भेजी जाएंगी।

आर्टेमिस II मिशन अपोलो के बाद पहली बार मानवयुक्त यान को चंद्रमा के पास ले जाने वाला है। चार सदस्यीय दल में रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन शामिल हैं।

सोलो ट्रिप का नया ऑप्शन बना कम्युनिटी ट्रैवल, क्यों अजनबियों के साथ घूमना पसंद कर रहे हैं Gen-Z?

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

आजकल के युवाओं, खासकर जेन–जी के बीच सफर करने का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। एक समय था जब ग्रुप टूर का नाम सुनते ही बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की तस्वीर जेहन में आती थी, लेकिन आज यह ट्रेंड युवाओं की पहली पसंद बन चुका है।

इसे कम्युनिटी ट्रैवल कहा जा रहा है, जहां अनजान लोग एक साथ मिलकर नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। सुनने में ऐसा लग सकता है कि लोग अजनबियों के साथ घूमने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर इसे ध्यान से समझें, तो इसके पीछे आज की पीढ़ी से जुड़ी एक बड़ी वजह है।

कम्युनिटी ट्रैवल घूमने का बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीका है। आप किसी ट्रैवल कंपनी के साथ अपनी पसंद की जगह के लिए साइन–अप करते हैं। आपके साथ दूसरे ट्रैवलर्स भी उसी ट्रिप का हिस्सा बनते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग अकेले आए होते हैं। यह पूरा ग्रुप मिलकर एक ही ट्रैवल प्लान फॉलो करके सफर करता है।

इस सफर की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मिलने वाली सुविधा। कंपनी आपकी लाइट्स, ठहरने की जगह, वीजा और घूमने की जगहों जैसे सभी लॉजिस्टिक्स को संभालती है। साथ ही, इन ट्रिप्स में एक ट्रिप कैप्टन भी होता है जो पूरे ग्रुप के साथ रहता है और पूरी ट्रिप को मैनेज करता है। इसके अलावा, लोकल गाइड भी होते हैं जो उस जगह के बारे में जानकारी देते हैं।

कम्युनिटी ट्रैवल को इतना पसंद किए जाने के पीछे एक

बड़ा कारण हमारी शहरी जीवनशैली है। आज के युवा ऑफिस या पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर अपने घर और पुराने दोस्तों को पीछे छोड़कर नए शहरों में बस जाते हैं। ऐसे में पुराने दोस्तों के साथ तालमेल बिठाना और ट्रिप प्लान करना मुश्किल हो जाता है। जब दोस्तों के साथ प्लान नहीं बन पाते, तो घूमने–फिरने के लिए कम्युनिटी ट्रैवल अच्छा ऑप्शन साबित होता है।

जेन–जी सोलो ट्रिप तो करना चाहती है, लेकिन सफर के दौरान अकेलेपन से भी बचना चाहती है। ऐसे में सफर के दौरान कोई दोस्त बनाना मुश्किल होता है, लेकिन कम्युनिटी ट्रैवल में साथ घूमने और एक्सपीरिएंस शेयर करने के लिए लोग मिल जाते हैं। इस दौरान नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है और एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसकी पसंद और सोच उनसे मिलती–जुलती होती है। यह अकेलापन दूर करने और सफर को रोमांचक बनाने का बेहतरीन तरीका बन गया है।

किडनी के मरीज अपनी डाइट में बैलेंस करें ये 4 जरूरी मिनरल्स, एम्स दिल्ली की डॉक्टर ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, 05 अप्रैल।

अगर आपकी फैमिली या जान–पहचान में कोई किडनी का मरीज है, तो उनके लिए सही और संतुलित डाइट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एम्स दिल्ली की एमडी मेडिसिन और डीएम न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ, डॉ. प्रियंका सहरावत के मुताबिक, किडनी के मरीजों को अपनी डाइट में मुख्य रूप से 4 मिनरल्स का खास ध्यान रखना चाहिए। जी हां– सोडियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम।

सोडियम– किडनी के मरीजों के लिए सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको पूरे 24 घंटे में 5 ग्राम से भी कम नमक का सेवन करना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा कम रखने से किडनी पर कम दबाव पड़ता है।

पोटैशियम– जब किडनी खराब होने लगती है, तो वह शरीर से पोटैशियम को सही से बाहर नहीं निकाल पाती है। इसके कारण खून में पोटैशियम जमा होने लगता है और इसका स्तर बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी डाइट में पोटैशियम से भरपूर चीजों को कम करना होगा। नारियल पानी, केला और एवोकाडो जैसी चीजों का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें।

फास्फोरस– डॉक्टर के अनुसार, किडनी के मरीजों के लिए फॉस्फोरस का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब किडनी फॉस्फोरस को शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है, तो यह खून में बढ़ने लगता है। इसके बढ़ने

से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में भयंकर दर्द रहने लगता है। इसे कम करने के लिए आपको अपनी डाइट से ये चीजें कम करनी होंगी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मेवे और बीज (जैसे कद्दू के बीज और अखरोट), बेकरी आइटम्स, पैकेज्ड फूड आदि।

कैल्शियम– किडनी के मरीजों में कॉम्प्लिकेशन के रूप में हड्डियों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। एक मरीज को दिन भर में 800 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। इस जरूरत को आप अपनी डाइट के जरिए या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेकर पूरा कर सकते हैं।

खून में इन 4 मिनरल्स का सही संतुलन बनाए रखना किसी भी किडनी के मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी डाइट में इन जरूरी बदलावों को अपनाकर बहुत सी शारीरिक तकलीफों से बचा जा सकता है।